सं. अ. 5-1/2022- ईई.1

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिसंबर, 2022 माह का कैबिनेट के लिए मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिसंबर 2022 के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित मासिक सार की एक प्रति कैबिनेट के लिए परिचालित करने का निर्देश हुआ

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

राजेश सैम्पले

(राजेश सैम्पले)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 011-23384589

सेवा में

1. सभी मंत्रिपरिषद
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग के सचिव।
3. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली।
4. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।

जानकारी के लिए कॉपी:

- माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
- राज्य मंत्री के निजी सचिव, शिक्षा मंत्रालय
- सचिव (एसईएंडएल) के पीपीएस

राजेश सैम्पले

(राजेश सैम्पले)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 011-23384589

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

मंत्रिमंडल हेतु दिसम्बर, 2022 **माह का मासिक सार**

दिसम्बर, 2022 के दौरान महत्वपूर्ण विकास और गतिविधियां

I. वित्तीय उपलब्धियां/जारी की गई:

31 दिसम्बर, 2022 तक बजट अनुमान का 61.18% जारी किया गया।

II. महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और गतिविधियां/पहल :

क. नीति संबंधी विचार-विमर्श/बैठकें:

महत्वपूर्ण मुद्दे/विकास

क्र. स.	विषय	सार
1	न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	इस विभाग द्वारा **30** दिसंबर, **2022** को न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के कार्यान्वयन के लिए मसौदा दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शिक्षा सचिवों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों/सिफारिशों के लिए **15** जनवरी, **2023** तक भेज दिए गए हैं।
2	स्टार्स	शिक्षा मंत्रालय और केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच संविदा समझौते पर 12 दिसंबर, 2022 को स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन की सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
3	पीएम श्री	पीएम श्री पोर्टल स्कूलों के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 3 नवंबर, 2022 को प्रारंभ किया गया है और वर्तमान में, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 1,65,381 स्कूलों ने अब तक आवेदन किया है।
4	एनईपी	• प्रथम राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में एनईपी चाइल्ड एनईपी स्कूल और एनईपी शिक्षक तीन विषयों के तहत अभिचिन्हित प्रत्येक

क्र. स.	विषय	सार
		प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कार्रवाई बिंदुओं पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी के लिए **1** दिसंबर, **2022** को एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। • जनवरी, 2023 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय मुख्य सचिवों के द्वितीय सम्मेलन के संबंध में सचिव, एसई एंड एल द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को दिनांक 09.12.2022 का एक अ.शा.पत्र जारी किया गया था।
5	पीएम पोषण पर दिशानिर्देश	पीएम पोषण योजना पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और **21** दिसंबर, **2022** को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया। ये दिशानिर्देश https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf पर उपलब्ध हैं।
6	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफईसीसीई)	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफईसीसीई), जिसे मूलभूत चरण कहा जाता है, चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं (एनसीएफ) में से एक है। यह भारत में 3-8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अब तक का प्रथम एकीकृत पाठ्यचर्या ढांचा है। यह **5+3+3+4 'पाठ्यक्रम और शैक्षणिक'** संरचना का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे एनईपी **2020** ने स्कूल शिक्षा के लिए अनुशंसित किया है। मूलभूत चरण के लिए एनसीएफ (एनसीएफएफएस) एनसीईआरटी द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आरंभिक स्तर पर और विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है। मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा **20** अक्टूबर, **2022** को नई दिल्ली में देश भर में प्रारंभ की गई थी।
7	स्कूल के लिए फुटबॉल (एफ4एस) कार्यक्रम	विश्व भर के स्कूली छात्रों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने स्कूल के लिए फुटबॉल (एफ4एस) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। इस संबंध में, भारत में कार्यक्रम को लागू करने के लिए फीफा, एआईएफएफ और इस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनवीएस ने देश भर के सभी जिलों में कार्यक्रम को लागू करने के लिए इस मंत्रालय से नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।